राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 647/2022

रानी जेंडा (श्रीमती) पुत्री श्री हीरालाल जी जेंडा पत्नी श्री हेमंत परिहार, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी हनुमान चौक, गंगलाव तालाब, चांदपोल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान।

3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली, राजस्थान।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: डॉ. निखिल डुंगावत।
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री महावीर बिश्नोई, एएजी श्री एचएस चुंडावत द्वारा सहायता प्राप्त।

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

01/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत 05.02.2021 (अनुलग्नक 7) और 23.03.2012 (अनुलग्नक 3) के आदेशों से उत्पन्न हुई है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी इस आधार पर

खारिज कर दी गई थी कि विवाहित बेटी को मृतक सरकारी कर्मचारी का आश्रित नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, वह प्रतिवादियों को उसके आवेदन पर पुनर्विचार करने और सभी परिणामी लाभों के साथ 28.10.2021 (अनुलग्नक 09) की अधिसूचना के अनुसार उसे अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश चाहती है।

2. याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता की मां उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत थीं, जब 02.11.2011 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता ने बेटी होने के नाते 25.01.2012 को एक आवेदन दिया और फिर 22.01.2021 को अनुकंपा नियुक्ति की मांग की। 2.1. 23.03.2012 (अनुलग्नक 2) को याचिकाकर्ता के आवेदन को दिनांक 05.02.2021 (अनुलग्नक 7) के आक्षेपित आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि मृतक कर्मचारी की विवाहित पुत्री होने के कारण उसे अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता।

2.2. 28.10.2021 (अनुलग्नक 9) को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत 1996 के नियमों में संशोधन किया गया और विवाहित पुत्री को भी मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित के रूप में शामिल किया गया। इसलिए, तत्काल याचिका।

3. हालांकि जवाब की प्रति रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन इसे याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को दिया गया था, जिन्होंने सुनवाई के दौरान इसकी एक फोटोकॉपी दी है।

3.1. इसके अवलोकन से पता चलता है कि लिए गए रुख का सार पैरा संख्या 4 में है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> “ 4. रिट याचिका के पैरा 4 में किए गए कथन इस सीमा तक स्वीकार किए जाते हैं कि विवाहित पुत्री आश्रित की श्रेणी में नहीं आती है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि राजस्थान मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 (जिसे आगे "नियम 1996" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अनुसार, मृतक सरकारी कर्मचारियों की विवाहित पुत्री अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रितों की श्रेणी में नहीं आती है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 28.10.2021 की अधिसूचना के अनुसार नियम 2 में संशोधन के बाद विवाहित पुत्री इस श्रेणी में आती है। इसलिए, यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार

पात्र नहीं था। तदनुसार, अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को दिनांक 23.03.2012 के आदेश के अनुसार सही रूप से खारिज कर दिया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि जब याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिनांक 23.03.2012 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, तो याचिकाकर्ता को वर्ष 2012 में ही इसे चुनौती देने की आवश्यकता थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने दस वर्षों से अधिक की अवधि के लिए इसे चुनौती नहीं दी है और अब यह रिट याचिका वर्ष 2022 में दायर की गई है, इसलिए याचिकाकर्ता की रिट याचिका देरी और लापरवाही के आधार पर खारिज कर दी जाएगी।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं और केस फाइल का अध्ययन किया है।

5. मैं शुरू से ही यह देखने के लिए बाध्य हूं कि उत्तर में प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए बचाव और याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने के बचाव में उनके तर्क, कम से कम कहने के लिए पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। आइए देखें कि कैसे।

6. प्रियंका श्रीमाली बनाम राजस्थान राज्य के मामले में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है: सिविल संदर्भ संख्या 01/2022 13.09.2022 को अन्य संबंधित मामलों के साथ तय किया गया, जिसमें स्पष्ट शब्दों में, पूर्ण पीठ के लिए बोलते हुए, मेरे विद्वान भाई अरुण भंसाली, जे., (जैसा कि उस समय उनके आधिपत्य इस न्यायालय में थे) ने निम्नलिखित राय दी:-

परिणामस्वरूप, संदर्भ का निपटारा किया जाता है। संदर्भ में पुनः तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया है:-

नियम 1996 के नियम 2(सी) का प्रावधान, जो दिनांक 28.10.2021 की अधिसूचना द्वारा संशोधन से पहले विवाहित पुत्री को आश्रित की परिभाषा से बाहर करता है, भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 का उल्लंघन करता है और इस प्रकार, 'आश्रित' की परिभाषा से 'अविवाहित' शब्द को हटा दिया जाता है। इसके अलावा, नियम 1996 के नियम 5 में भी अविवाहित पुत्रियाँ/दत्तक अविवाहित पुत्री शब्द को पुत्रियाँ/दत्तक पुत्री के रूप में पढ़ा जाएगा।

सुमेर कंवर (सुप्रा) के मामले में निर्णय और अन्य सभी निर्णय, जो सुमेर कंवर (सुप्रा) के मामले में निर्णय का अनुसरण करते हैं, जिसमें विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने को बरकरार रखा गया है, को खारिज कर दिया जाता है।

परिणामस्वरूप, यह निर्देश दिया जाता है कि परिभाषा से 'अविवाहित' शब्द को हटाने के कारण - (i) यह किसी ऐसे मामले को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें इस आदेश से पहले के प्रावधानों के तहत अनुकंपा नियुक्ति पहले ही दी जा चुकी है; (ii) यह अपने आप में किसी भी आवेदक को कार्रवाई का कारण नहीं देगा और केवल उन मामलों पर लागू होगा जो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं और/या उन मामलों पर जहां इस आदेश की तिथि पर मुकदमा लंबित है; (iii) आवेदक की मृत्यु के समय मृतक सरकारी कर्मचारी पर पूरी तरह से आश्रित होने के संबंध में परिभाषा के प्रावधानों और अन्य आवश्यकताओं को ईमानदारी से लागू किया जाएगा; (iv) अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों का भी ईमानदारी से पालन किया जाएगा और (v) 'आश्रित' की परिभाषा में 'विवाहित बेटी' को शामिल करने के अलावा नियमों के अन्य सभी प्रावधान पूरी तरह से लागू होंगे।

अब मामलों को उचित आदेशों के लिए डिवीजन बेंच के समक्ष रखा जाए।

7. उपरोक्त के आलोक में, तत्काल रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और दिनांक 23.03.2012 (अनुबंध 3) और 05.02.2021 (अनुबंध 7) के आरोपित आदेशों को आगामी परिणामों के साथ रद्द किया जाता है।

8. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर प्रियंका श्रीमाली (सुप्रा) के मामले में पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुरूप विचार किया जाएगा और राजस्थान मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 2 सी (iii) के अनुसार याचिकाकर्ता की वित्तीय स्थिति के सत्यापन के अधीन होगा, जैसा कि पूर्ण पीठ के निर्णय में उल्लेख किया गया है।

9. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।